Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

12 नवंबर 2026 • हिंदी

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 10 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

1 अक्टूबर 2026 में अखिल भारतीय सीपीआई (आधार 2024=100) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 6.09 प्रतिशत (अनंतिम); सीएफपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 8.94 प्रतिशत

All-India CPI inflation (base 2024=100) for October 2026 is 6.09% (provisional); food inflation based on CFPI is 8.94%

SSC • Banking • Railway • General

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने 12 नवंबर 2026 को अक्टूबर 2026 के लिए आधार 2024=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जारी किया। आधार वर्ष 2024 वाले अखिल भारतीय सीपीआई पर आधारित अक्टूबर 2025 की तुलना में अक्टूबर 2026 की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर 6.09 प्रतिशत (अनंतिम) है; ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 6.63 प्रतिशत और 5.41 प्रतिशत हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित अक्टूबर 2026 की वर्ष-दर-वर्ष खाद्य मुद्रास्फीति 8.94 प्रतिशत (अनंतिम) है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दरें क्रमशः 9.09 प्रतिशत और 8.68 प्रतिशत हैं। रिलीज़ में सितंबर 2026 की अंतिम संयुक्त सीपीआई मुद्रास्फीति 5.54 प्रतिशत बताई गई है। अखिल भारतीय संयुक्त स्तर पर प्रमुख वस्तुओं में उच्च मुद्रास्फीति वाली वस्तुओं की सूची में प्याज (116.22 प्रतिशत) सबसे ऊपर है, जबकि निम्न मुद्रास्फीति वाली वस्तुओं की सूची में आलू (-14.24 प्रतिशत) सबसे ऊपर है। एनएसओ, एमओएसपीआई के क्षेत्र संकार्य प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी 1407 शहरी बाजारों (ऑनलाइन बाजारों सहित) और 1465 गांवों से कीमतें एकत्र करते हैं, और अक्टूबर 2026 में ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में प्रतिक्रिया दर 100 प्रतिशत रही। रिलीज़ के अनुसार नवंबर 2026 का सीपीआई 14 दिसंबर 2026 को जारी किया जाएगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335416

2 भारी उद्योग मंत्रालय को पीएलआई एसीसी योजना के तहत 10 जीडब्ल्यूएच एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) विनिर्माण क्षमता के लिए 22 बोलियां प्राप्त हुईं

Ministry of Heavy Industries receives 22 bids for 10 GWh Advanced Chemistry Cell (ACC) manufacturing capacity under the PLI ACC Scheme

SSC • Banking • Railway • General

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को भारत में गीगा-स्तरीय एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने हेतु लाभार्थी कंपनियों के चयन के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर जारी वैश्विक निविदा के तहत प्रस्तावित 10 जीडब्ल्यूएच क्षमता के लिए संभावित बोलीदाताओं से 22 बोलियां प्राप्त हुई हैं। यह 10 जीडब्ल्यूएच क्षमता ग्रिड-स्केल स्थिर भंडारण (जीएसएसएस) अनुप्रयोगों के लिए निर्धारित है और 'एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' के तहत लक्षित कुल 50 जीडब्ल्यूएच एसीसी विनिर्माण क्षमता का हिस्सा है; केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ इस उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी थी। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) 15 जुलाई 2026 को जारी किया गया, बोली-पूर्व सम्मेलन 29 जुलाई 2026 को हुआ, बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 थी, और तकनीकी बोलियां 11 नवंबर 2026 को एमएचआई में बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली गईं। बोली प्रक्रिया दो चरणों वाली गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जा रही है; बोलीदाताओं में एक्मे (ACME) सोलर होल्डिंग्स, अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजीज, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस शामिल हैं। यह बोली का चरण है: रिलीज़ में किसी चयनित लाभार्थी का नाम नहीं दिया गया है। रिलीज़ के अनुसार जीएसएसएस के लिए 10 जीडब्ल्यूएच के आवंटन से नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से उत्पन्न देश की बढ़ती ऊर्जा-भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335459

3 केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 13 नवंबर को 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन करेंगे; आईआईटीएफ 2026 का आयोजन 14 से 27 नवंबर तक भारत मंडपम में होगा

Union Commerce and Industry Minister Shri Piyush Goyal to inaugurate the 45th India International Trade Fair on 13 November; IITF 2026 to be held at Bharat Mandapam from 14 to 27 November

SSC • Railway • General

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित 45वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2026, 14 से 27 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 13 नवंबर 2026 को मुख्य अतिथि के रूप में मेले का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में पद्मश्री से सम्मानित गुरु माधवी मुद्गल और उनके समूह द्वारा ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति भी दी जाएगी। 'विकास और विरासत' विषय पर आधारित आईआईटीएफ 2026 में भारत और विदेशों के 3,500 से अधिक प्रदर्शक 17 हॉल में 1,00,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रदर्शनी क्षेत्र में भाग लेंगे। मेले में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 51 केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी होगी। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश साझेदार राज्य होंगे, जबकि असम, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल फोकस राज्य होंगे, और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत 11 देश शामिल होंगे। हॉल संख्या 14 में स्थित हॉल ऑफ इंस्पिरेशन में लगभग 600 भारतीय स्टार्टअप प्रदर्शित किए जाएंगे, और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) मंडप में 21 राज्यों की भागीदारी होगी। पहले पांच दिन, 14 से 18 नवंबर तक, व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) आगंतुकों के लिए आरक्षित व्यावसायिक दिवस होंगे, और 19 से 27 नवंबर तक मेला आम जनता के लिए खुला रहेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335428

4 केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन किया

Union Commerce Minister Shri Piyush Goyal inaugurates the 31st CII Partnership Summit at Visakhapatnam along with Andhra Pradesh Chief Minister Shri N Chandrababu Naidu

SSC • Banking • Railway • General

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ 12 नवंबर 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 31वें पार्टनरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दुनिया में अस्थिरता, संघर्ष और अनिश्चितता के बावजूद भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक पूर्वानुमेय, भरोसेमंद और उच्च क्षमता वाला गंतव्य बना हुआ है, और उन्होंने निवेशकों को तीन आश्वासन दिए: खुला बाजार, क्षमता और विश्वसनीयता। खुले बाजार के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में भारत ने 38 देशों को शामिल करते हुए नौ मुक्त व्यापार समझौते या तरजीही व्यापार समझौते किए हैं, जो वैश्विक जीडीपी के 60 ट्रिलियन डॉलर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जारी बातचीत के साथ यह आंकड़ा बढ़कर 85 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो 115 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक जीडीपी का लगभग तीन-चौथाई है; उन्होंने कहा कि इससे देश के 2.5 लाख स्टार्टअप के लिए अवसर खुलते हैं। उन्होंने निवेशकों को प्रोत्साहन राशि के समय पर भुगतान के लिए राज्य की एस्क्रो खाता व्यवस्था की भी सराहना की। रिलीज़ के अनुसार 'Navigating the New World Order: Trade, Technology, Trust and Thought Leadership' (नई विश्व व्यवस्था में आगे बढ़ना: व्यापार, प्रौद्योगिकी, विश्वास और वैचारिक नेतृत्व) विषय पर आधारित इस दो दिवसीय समिट का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार और सीआईआई संयुक्त रूप से कर रहे हैं, और इसमें लगभग 60 देशों के नीति निर्माता, मंत्री और उद्योग जगत के प्रमुख एक साथ आए हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335391

5 टीडीबी-डीएसटी ने सॉवरेन अंतरिक्ष-आधारित एआई-ईएलआईएनटी समूह विकसित करने के लिए आरडीआई फंड के तहत 64.05 करोड़ रुपये की सहायता हेतु एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए

TDB-DST signs agreement with Astrome Technologies for ₹64.05 crore support under the RDI Fund to develop a sovereign space-based AI-ELINT constellation

SSC • Railway • Science • Defence • General

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 12 नवंबर 2026 को बताया कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) फंड के तहत 64.05 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए मैसर्स एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 128.11 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए एक सॉवरेन अंतरिक्ष-आधारित एआई-ईएलआईएनटी समूह (कॉन्सटीलेशन) विकसित करना है। यह परियोजना प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (टीआरएल)-4 से टीआरएल-9 तक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने का प्रयास है, और वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (ओसीडी) के माध्यम से दी जा रही है। कार्यक्रम तीन प्रमुख प्रौद्योगिकी घटकों को एक साथ लाता है: एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस (ईएलआईएनटी) पेलोड, जिसका उद्देश्य व्यापक आवृत्ति रेंज में संकेतों का पता लगाने और उनके विश्लेषण में सहायता करना है; समूह द्वारा उत्पन्न जानकारी के लिए ग्राउंड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर; और अंतर-उपग्रह संचार लिंक, जिनसे उपग्रह आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान कर एक एकीकृत नेटवर्क के रूप में काम कर सकेंगे। परियोजना में पृथ्वी की निचली कक्षा में काम करने वाले 50 किलोग्राम वर्ग के माइक्रोसैटेलाइट के विकास और चरणबद्ध तैनाती की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त उपग्रहों की तैनाती के साथ कवरेज और पुनरीक्षण क्षमता को उत्तरोत्तर बढ़ाना है। यह परियोजना गहन प्रौद्योगिकी (डीप टेक्नोलॉजी) क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसका उप-क्षेत्र अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने कहा कि आरडीआई फंड के माध्यम से टीडीबी अग्रणी प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले उन भारतीय उद्यमों का समर्थन कर रहा है जो देश की रणनीतिक प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335322

6 सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार नशा मुक्त भारत अभियान 35.88 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा, जिनमें 14.35 करोड़ से अधिक युवा और 11.33 करोड़ महिलाएं शामिल

Nasha Mukt Bharat Abhiyaan reaches over 35.88 crore people, including over 14.35 crore youth and 11.33 crore women, says Social Justice Ministry

SSC • Railway • Banking • General

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि उसके द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 12 नवंबर 2026 तक देश भर में 35.88 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। अभियान 14.35 करोड़ से अधिक युवाओं और 11.33 करोड़ महिलाओं से जुड़ा है, और 2 लाख से अधिक नागरिकों ने नशा मुक्ति मित्र के रूप में पंजीकरण कराया है; ये सामुदायिक स्वयंसेवक जागरूकता फैलाने में योगदान देते हैं और लोगों को सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह अभियान शुरुआत में मादक पदार्थों के सेवन की दृष्टि से विशेष रूप से संवेदनशील पहचाने गए 272 जिलों में शुरू किया गया था, अगस्त 2022 में इसे 372 जिलों तक बढ़ाया गया और 15 अगस्त 2023 से इसे देश के सभी जिलों तक विस्तारित कर दिया गया; 2021 में लगभग 1.4 करोड़ लोगों तक पहुंच की तुलना में इसका दायरा काफी बढ़ा है। शैक्षणिक संस्थानों में 34.07 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई हैं। अधिकारी ने याद दिलाया कि भारत में मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर 2018 में किए गए पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण से संकेत मिला था कि देश में 7 करोड़ से अधिक लोग मादक पदार्थों के सेवन से जुड़े विकारों से प्रभावित थे, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं। एनएमबीए नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के तहत प्रमुख जागरूकता पहल है, जो रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर केंद्रित है। अधिकारी के अनुसार उपचार और परामर्श लेने वाले लोगों की संख्या 2020-21 में 2.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक हो गई है, और देश में जिला नशा मुक्ति केंद्रों की कुल संख्या अब 198 है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335430

7 शिक्षा मंत्रालय के अनुसार आईआईटी खड़गपुर एनएमसी से मान्यता प्राप्त एमडी कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला आईआईटी बना, 2026-27 सत्र से 12 सीटें

IIT Kharagpur becomes the first IIT to introduce NMC-accredited MD programmes, with 12 seats from the 2026-27 session, says Education Ministry

SSC • Railway • General

पीआईबी कोलकाता द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी शिक्षा मंत्रालय की रिलीज़ के अनुसार देश का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी खड़गपुर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला आईआईटी बन गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संस्थान आईआईटी खड़गपुर के तत्वावधान में संचालित डॉ. बी. सी. रॉय मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर, खड़गपुर में एमडी विद्यार्थियों के अपने पहले बैच का स्वागत करेगा। एमडी कार्यक्रम छह विषयों में हैं, जिनमें से प्रत्येक में दो सीटें हैं: जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और बायोकेमिस्ट्री; कुल प्रवेश क्षमता 12 सीटें है। 2026-27 के लिए प्रवेश नीट-पीजी 2026 ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से होंगे, और ये कार्यक्रम आधिकारिक काउंसलिंग समय-सारिणी, पात्रता शर्तों और सीट मैट्रिक्स के अनुसार दूसरे दौर (राउंड 2) में विचार के लिए उपलब्ध होंगे; अभ्यर्थियों से सीटों की उपलब्धता, विकल्प भरने, पात्रता और काउंसलिंग की तारीख़ों के लिए आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल देखने को कहा गया है। रिलीज़ के अनुसार पहला बैच भारत की आईआईटी प्रणाली के इतिहास में स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थियों की पहली पीढ़ी होगा, और विद्यार्थी अगली पीढ़ी की मेडिकल इमेजिंग, कम्प्यूटेशनल पैथोलॉजी, बायोमेडिकल उपकरण, आणविक निदान और प्रिसिजन मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान से जुड़ सकेंगे। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। इसके निदेशक प्रो. सुमन चक्रवर्ती ने कहा कि उद्देश्य केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रशिक्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां नैदानिक उत्कृष्टता इंजीनियरिंग और ट्रांसलेशनल अनुसंधान से जुड़े।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335480

8 रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने नए स्वरूप वाले वीरता पुरस्कार पोर्टल का शुभारंभ किया

Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth launches the revamped Gallantry Awards portal

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में नए स्वरूप वाले वीरता पुरस्कार पोर्टल (gallantryawards.gov.in) का शुभारंभ किया। यह पोर्टल वीरता पुरस्कार विजेताओं के साहस और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने और उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने की एक समर्पित डिजिटल पहल है। नए सिरे से विकसित पोर्टल में सहज नेविगेशन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और बेहतर सुगम्यता के साथ उन्नत, नागरिक-केंद्रित यूज़र इंटरफ़ेस और यूज़र अनुभव है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में आयोजन (इवेंट्स), स्मारक और संग्रहालय, वॉरपीडिया, पुरस्कार विजेता, गैलेंट्रीपीडिया (लेख), मीडिया और एक इंटरैक्टिव श्रद्धांजलि अनुभाग जैसे समर्पित खंड शामिल हैं, जिनके माध्यम से नागरिक देश के सैन्य इतिहास को जान सकते हैं और उसके वीरों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। पोर्टल पर वीर गाथा के लिए भी एक समर्पित डिजिटल स्थान है, जिसमें हर संस्करण का एक पेज है और उस पर उसका परिचय, विषय, समय-सारिणी, मूल्यांकन मानदंड, पुरस्कार, संसाधन, परिणाम, सम्मान समारोह, मीडिया गैलरी और विद्यार्थियों की गतिविधियां एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं; इसके माध्यम से विद्यार्थी वीरता पुरस्कार विजेताओं के साहस और बलिदान के बारे में जानते हैं और अपनी प्रविष्टियों के जरिए अपनी सीख व्यक्त करते हैं। मंत्रालय के अनुसार यह कार्यक्रम पहले संस्करण के लगभग 8 लाख विद्यार्थियों और 4,788 स्कूलों से बढ़कर पांचवें संस्करण में 1.92 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों और 1.9 लाख स्कूलों तक पहुंच गया है; कार्यक्रम में 18 देशों के 91 सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों के 28,005 विद्यार्थी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद से वीरता पुरस्कारों, पुरस्कार विजेताओं, युद्धों और सैन्य अभियानों की जानकारी का एक व्यापक और प्रामाणिक डिजिटल भंडार तैयार करना है। इस अवसर पर रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335471

9 नीति आयोग ने आईआईएम अहमदाबाद को ज्ञान भागीदार बनाकर तैयार की गई 'पीएलआई योजनाओं के प्रभाव का आकलन' रिपोर्ट जारी की; रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत लक्षित क्षेत्रों में प्रगति लक्ष्य के अनुरूप

NITI Aayog releases its report 'Impact Assessment of PLI Schemes', prepared with IIM Ahmedabad as knowledge partner; nearly 70% of targeted segments on track, the report finds

SSC • Banking • Railway • General

नीति आयोग ने 12 नवंबर 2026 को 'पीएलआई योजनाओं के प्रभाव का आकलन' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जो भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद के सहयोग से तैयार की गई है, जिसने इसमें ज्ञान भागीदार के रूप में काम किया। रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का क्षेत्रवार आकलन किया गया है, जिसमें निवेश, अतिरिक्त उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया है। यह आकलन संबंधित मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए कंपनियों के आंकड़ों और प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त उद्योग जगत की जानकारियों पर आधारित है, और क्षेत्रों के परिणामों को चार श्रेणियों में बांटा गया है: लक्ष्य के अनुरूप प्रगति, आंशिक प्रभाव, प्रभाव के नगण्य प्रमाण और आंकड़े उपलब्ध नहीं। रिपोर्ट के अनुसार दवा उद्योग, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम) के तहत मोबाइल निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार, घरेलू उपयोग के उपकरण (व्हाइट गुड्स), वाहन और ड्रोन क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन और विनिर्माण क्षमता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और ड्रोन क्षेत्र शुरुआती सफल उदाहरण के रूप में उभरा है; उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल की विनिर्माण क्षमता में काफी विस्तार हुआ है; तथा एसीसी बैटरी, विशेष इस्पात और तकनीकी वस्त्र जैसे क्षेत्रों में धीरे-धीरे विनिर्माण क्षमता और औद्योगिक तंत्र का विकास हो रहा है। रिपोर्ट के समग्र क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत लक्षित क्षेत्रों में प्रगति लक्ष्य के अनुरूप है। रिपोर्ट के अनुसार योजना ने निवेश और उत्पादन को निर्धारित लक्ष्यों से आगे बढ़ाया है, हालांकि इसकी दीर्घकालिक सफलता घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखला के मजबूत होने पर निर्भर करेगी; रिपोर्ट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की अधिक भागीदारी, आंकड़ों की एकसमान व्यवस्था और औद्योगिक तंत्र के निरंतर विकास के महत्व पर जोर दिया गया है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335594

10 डब्ल्यूएचओ की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2026 में वर्ष 2015 के बाद से भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की कमी और 94 प्रतिशत उपचार सफलता दर रेखांकित: स्वास्थ्य मंत्रालय

WHO Global Tuberculosis Report 2026 highlights a 38% reduction in India's TB mortality since 2015 and a 94% treatment success rate, says Health Ministry

SSC • Railway • Banking • General

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 नवंबर 2026 को उसी दिन जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2026 का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2015 के बाद से भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर 35 प्रतिशत की कमी आई है, और दवा-संवेदी टीबी (जिसमें टीबी रोधी दवाएं असरदार रहती हैं) के मरीजों में उपचार की सफलता दर 94 प्रतिशत है। रिपोर्ट में भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली (आरजीआई/एसआरएस), समुदाय के स्तर पर बातचीत के जरिए मृत्यु के कारणों के आकलनों (वर्बल ऑटोप्सी) और नि-क्षय पोर्टल के कार्यक्रम संबंधी आंकड़ों से प्राप्त साक्ष्यों का उपयोग किया गया है, और मंत्रालय के अनुसार इसमें भारत में टीबी से होने वाली अनुमानित मौतों में 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है: वर्ष 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर मौतों की संख्या 28 थी, जो वर्ष 2025 में घटकर प्रति लाख जनसंख्या पर 18 रह गई। मंत्रालय के अनुसार टीबी कार्यक्रम की वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं का 96 प्रतिशत हिस्सा घरेलू संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पहला 100 दिवसीय गहन अभियान 7 दिसंबर 2024 को 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 347 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में शुरू किया गया और बाद में इसका विस्तार पूरे देश में किया गया, तथा 24 मार्च 2026 को एक अन्य 100 दिवसीय गहन अभियान शुरू किया गया, जिसमें 1.58 लाख उच्च जोखिम वाले गांवों और वार्डों में टीबी की जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया। 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच 25 करोड़ से अधिक लोगों को टीबी जांच के दायरे में लाया गया, 11 करोड़ से अधिक छाती के एक्स-रे और 3 करोड़ से अधिक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन परीक्षण (एनएएटी) किए गए, और टीबी के 48.64 लाख नए मामलों की पहचान की गई, जिनमें 14.97 लाख बिना लक्षण वाले मामले शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआरटी) ने वर्ष 2025 में टीबी के फैलाव का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि सर्वेक्षण किया, जिसके निष्कर्ष डब्ल्यूएचओ के साथ साझा किए जा चुके हैं और उन पर तकनीकी विचार-विमर्श जारी है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335615

आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

प्र.1 13 से 26 नवंबर 2026 तक होने वाला 12वां भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति 2026' कहां आयोजित किया जा रहा है?

(A) महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान
(B) फॉरेन ट्रेनिंग नोड, बेलगावी, कर्नाटक
(C) पनागोडा छावनी, कोलंबो, श्रीलंका
(D) आर्मी प्रशिक्षण विद्यालय, मदुरु ओया, श्रीलंका

प्र.2 विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में भारत ने कितने देशों को शामिल करते हुए कितने मुक्त व्यापार या तरजीही व्यापार समझौते किए हैं?

(A) ग्यारह, 85 देशों को शामिल करते हुए
(B) सात, 38 देशों को शामिल करते हुए
(C) नौ, 60 देशों को शामिल करते हुए
(D) नौ, 38 देशों को शामिल करते हुए

प्र.3 शिक्षा मंत्रालय की रिलीज़ के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री (एमडी) कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला आईआईटी कौन-सा बना है?

(A) आईआईटी दिल्ली
(B) आईआईटी खड़गपुर
(C) आईआईटी मद्रास
(D) आईआईटी बॉम्बे

प्र.4 आईएनएस सूरत 8 नवंबर 2026 को 'नसीम अल बह्र' के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा। यह भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है?

(A) सऊदी अरब
(B) ओमान
(C) संयुक्त अरब अमीरात
(D) कतर

प्र.5 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित रबी 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक) के लिए पीएंडके उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग कितनी है?

(A) 24,417.73 करोड़ रुपये
(B) 26,370.02 करोड़ रुपये
(C) 62,370.02 करोड़ रुपये
(D) 37,952.29 करोड़ रुपये

उत्तर: 1-(D) 2-(D) 3-(B) 4-(B) 5-(C)

रोज़ सुबह 7 बजे यही PDF Telegram पर: t.me/parikshasaathiapp — चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भेजें

रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/

वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)

ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। प्रकाशक: Mahesh Srivastava, Founder. सामग्री आधिकारिक विज्ञप्तियों से AI की सहायता से तैयार; किसी विषय-विशेषज्ञ संपादक द्वारा समीक्षित नहीं। ग़लती दिखे तो parikshasaathi.com/contact/ पर बताएँ।